अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था अब दुनिया की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली नहीं रह गई है। 2016 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.6 फीसद रही और चीन ने उसे इस मामले में पछाड़ दिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती बरकरार है। इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां खर्च कम करने के लिए छंटनी पर उतारू हैं। कुछ समय के लिए ही सही नोटबंदी के बाद 4 करोड़ आबादी को रोजगार देने वाला रियल एस्टेट सेक्टर सुस्ती में है। नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में एक फरवरी को पेश होने वाला बजट बेहद अहम है। इस बार सरकार के सामने दोहरी चुनौती होगी। उसे जनता को तत्काल राहत भी देनी है और सख्त बजट और कुशल टैक्स प्रणाली से दीर्घकालिक विकास लक्ष्य भी साधना है।

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं।

11

दैनिक जागरण

29 जनवरी 2017

स्वास्थ्य और असंगठित क्षेत्र बनें प्राथमिकता

2017-18 का आम बजट ऐसे समय आ रहा है जब सरकार अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के लिए प्रयासरत है। इस ओर सरकार अपना पहला कदम नोटबंदी के साथ ही उठा चुकी है।

सोना मित्रा
सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटबिलिटी

बजट से उम्मीद है कि कर्ज की दरें सस्ती करके नोटबंदी की मार झेल रहे छोटे किसानों व व्यापारियों को राहत दी जाएगी। वहीं मनरेगा योजना के लिए ज्यादा फंड आवंटित करके व मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ाकर उन्हें सशक्त किया जाएगा।

इस कदम के पीछे सरकार का दूसरा मकसद था अर्थव्यवस्था से कालेधन को बाहर निकालना। ऐसे दावे किए गए थे कि नोटबंदी के बाद सरकार के पास अतिरिक्त राजस्व आएगा जिसका इस्तेमाल समाज के निचले तबके के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर किया जा सकेगा। इन दावों पर बीते दिनों काफी बहस हुई हैं। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है अतिरिक्त राजस्व का। दरअसल राजस्व की कमी की वजह से समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं को पर्याप्त फंड आवंटित नहीं किया जाता है। इस लिहाज से भी यह बजट महत्वपूर्ण है।

यहां इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि 14वें वित्त आयोग के सुझावों के आधार पर जब 2015-16 से केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ा दी, तब से केंद्र द्वारा संचालित सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख स्कीमों और योजनाओं के लिए फंड की कमी होने लगी। इसमें समेकित बाल विकास योजनाएं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी पोषण व स्वास्थ्य से जुड़ी दो स्कीम शामिल हैं। राज्यों को अतिरिक्त राजस्व देने के पीछे यह तर्क दिया गया कि ज्यादा राजस्व के साथ इन योजनाओं को जारी रखने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी जाएगी। साथ ही इन योजनाओं के लिए राज्य अपने राजस्व में से फंड निकालेंगे। हालांकि देश को कैशलेस और डिजिटल अर्थव्यवस्था में तब्दील करने की सरकार की दलीलों को देखकर इस साल के बजट से उम्मीद की जा रही है कि नोटबंदी से मिले अतिरिक्त राजस्व को लेकर बजट रणनीति थोड़ी अलग होगी।

मीडिया में आ रही खबरों की मानें तो नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है। खासतौर पर ग्रामीण उम्मीद से अधिक प्रभावित हुआ है। इस आधार पर माना जा रहा है कि बजट में ग्रामीणों और गरीब तबके को कैश ट्रांसफर के माध्यम से राहत दी जा सकती है। इस बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की संभावित घोषणा को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण के बाद लोगों में इस योजना को लेकर उम्मीद जागी। भाषण में प्रधानमंत्री ने संकेत दिए थे कि गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 6000 रुपये किया जाएगा। ये योजना पूरे देश में लागू होगी। ऐसा कदम निश्चित रूप से सराहना के योग्य होगा क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत इस स्कीम को देशभर में समान रूप से लागू करने की बात कही जा चुकी है। सरकारी योजनाओं की विभिन्न स्कीमों में दिव्यांगों, एकल महिला/विधवा व बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कैश ट्रांसफर का प्रावधान भी मौजूद है। ऐसे में सभी खासतौर से ग्रामीणों के लिए बिना शर्त वाली एक समान कैश ट्रांसफर योजना स्वागत योग्य होगी।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उन लोगों को सहायता देने की बात कही थी जिन्होंने नोटबंदी के चलते नुकसान झेला। इसमें छोटे किसान, लघु व छोटे व्यापारी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर शामिल हैं। इस बजट से उम्मीद है कि कर्ज की दरों को घटाकर किसानों व व्यापारियों को राहत दी जाएगी। वहीं मनरेगा योजना के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित करके व मजदूरों की प्रतिदिन आय बढ़ाकर उन्हें सशक्त किया जाएगा। ग्रामीणों की तकलीफों को कम करने के लिए ऐसा कदम उठाना बेहद जरूरी है।

इस साल के बजट को स्वास्थ्य व पोषण आहार की योजनाओं पर पिछले कई बजट की तुलना में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल देश शिशु व मातृ मृत्यु दर को रोकने के अपने सतत विकास लक्ष्यों से पीछे चल रहा है। संक्रामक व असंक्रामक रोगों से निबटने के लिए इन लक्ष्यों के तहत स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा व पोषण जैसे विषयों पर कार्य किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य पर बजटीय आवंटन कुल सकल घरेलू उत्पाद का महज एक फीसद रहा है। यह आंकड़ा न सिर्फ अपर्याप्त है बल्कि तेजी से बढ़ती दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम भी है। बजट से अपेक्षा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बने बनाए ढांचे से बाहर निकलकर स्वास्थ्य सेवाओं को भी समूचे देश में एक बराबर लागू किया जाएगा और कम से कम जीडीपी का 2.5 फीसद स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में बजट से अपेक्षा है कि डिजिटल साक्षरता और इससे जुड़ी योजनाओं के लिए भी ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी। इसके अलावा बजट से यह भी आशा है कि महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों जैसे कि ग्रामीण विकास, कृषि और स्वास्थ्य व पोषण को भी प्रमुखता दी जाएगी। बजट 2017-18 से एक बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। इसमें योजनागत और गैर-योजनागत खर्च को अलग-अलग नहीं दिखाया जाएगा। इन दोनों के विलय से बजट की रणनीति और वित्तीय नीतियों पर खास फर्क नहीं पड़ेगा। खासतौर पर योजना आयोग की गैर मौजूदगी में उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट में समाज के निचले वर्ग के लिए लागू की गई अनुसूचित जाति सब प्लान और जनजाति सब प्लान जैसी योजनाओं का भविष्य स्पष्ट हो जाएगा।

...इसलिए खास रहे ये आम बजट

1991 में देश वित्तीय संकट में था। विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका था। केवल एक सप्ताह के आयात भुगतान लायक विदेशी मुद्रा बची थी। इस आपातकाल से लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के पास अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। तब तक देश को समझ आ चुका था कि वैश्वीकरण के दौर में बिना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अस्तित्व बनाए रखना बेहद मुश्किल होगा।

अरुण जेटली

2016

कर दाताओं को अपनी अघोषित आय की सूचना देकर 30 फीसद कर चुकाने का विकल्प दिया गया।

- पहली बार बजट में सनसेट क्लॉज आया। इसके मुताबिक किसी भी योजना के शुरू होते ही इसे पूरा करने की अवधि तय की जानी थी।

2015

- खत्म किया गया संपत्ति कर। सेवा कर बढ़ाकर 14 फीसद किया गया
- स्वच्छ भारत अभियान में योगदान करने पर सौ फीसद कर छूट

2014

नई यूरिया नीति और रक्षा क्षेत्र में 49 फीसद के विदेशी निवेश का प्रस्ताव

पी चिदंबरम

2013

प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रस्ताव, 1000 करोड़ रुपये का निर्भया फंड

प्रणब मुखर्जी

2012